

‘केंद्रीय बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम’

पीएम मोदी ने भारत की अंतरिक्ष और अंतरराष्ट्रीय नीति पर किया फोकस, परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था हुई मजबूत : राव राजेंद्र सिंह शेखावत

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर भाजपा जयपुर दक्षिण जिला की ओर से प्रबुद्धजन सम्मेलन तथा प्रेसवार्ता आयोजित की गई। प्रबुद्धजन सम्मेलन में सांसद मंजू शर्मा और राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने तथा कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बजट को सर्वेसर्वा, सर्व समावेशी बताते हुए विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने वाला बताया। इस दौरान विधायक कैलाश वर्मा, जयपुर दक्षिण जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने भी बजट को लेकर चर्चा की।



भाजपा प्रदेश कार्यालय में सांसद राव राजेंद्र सिंह ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद थे।

■ ‘मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के नेतृत्व में राजस्थान के विकास में देखने को मिली गति’

इससे भारत विकसित देशों के साथ बराबर खड़ा हो पाया है। यह देश के स्वाभिमान और स्वातंत्र्य की परिधी को परिभाषित करता है। सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने पांव मजबूत किए हैं। आज भारत नासा की तुलना में कई गुणा कम लागत पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहा है, ऐसे में विश्व के कई देश हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। यह विश्व में हमारे मजबूत अंतरिक्ष नीति को दर्शाता है। इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। भारत स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर के क्षेत्र में अपनी नई पॉलिसी के साथ कार्य कर रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और हम विकसित भारत 2047 के सपने का साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास की गति देखने को मिल रही है। भाजपा सरकार का लक्ष्य 350 बिलियन डॉलर तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है, उसकी तुलना में हम 50 फीसदी से ज्यादा पहुंच चुके हैं और अगले चार साल में इस लक्ष्य को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने प्रदेश की जनता को केंद्रित करते हुए अपने पिछले दो बजट पेश किए। इसमें किसानों की आय बढ़ाने के साथ, आधारभूत व्यवस्था में निवेश, अन्नदाता के खेत से लेकर आमजन के घर तक शुद्ध जल पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। भाजपा सरकार ने यमुना, चंबल और साबरमती परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाते हुए विकसित भारत की पृष्ठभूमि में विकसित राजस्थान की व्यवस्था को सुसज्जित करने का काम किया है। कार्यक्रम में जयपुर दक्षिण जिला प्रभारी विमल अग्रवाल, पूर्व विधायक निर्मल कुमार, संयोजक हृदय सुमन पारीक भी मंच पर उपस्थित रहे।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में अपनी अलग पहचान बना रही है। देश के जबतक केंद्रीय नेतृत्व के चलते आज हम विश्व की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हैं, और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना को

साकार करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है। इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान के सपने के लिए हर वर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया।

सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले किसी ने भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नीति और भारत की अंतरिक्ष नीति पर काम नहीं किया लेकिन मोदी सरकार ने इन दोनों नीतियों पर कार्य किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

करतारपुरा नाले को पक्का करने और प्रभावित मकानों को तोड़ने का मामला सदन में उठा

जयपुर। जयपुर के करतारपुरा नाले की चौड़ाई बढ़ाने और उसके पक्का करने के लिए जिन्हें मकानों को तोड़ना पड़ा है, उसका मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में उठा। मालवीय नगर क्षेत्र से बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए ये मामला उठाते हुए कहा- करतारपुरा नाले की चौड़ाई 30 मीटर करने के कारण 500 मकान टूटेंगे। 500 मकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं, जिससे लोगों में दहशत है।

■ विधायक सराफ ने कहा, “500 मकानों पर लाल निशान लगाने से लोग दहशत में हैं”

■ यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा, “हाईकोर्ट में रिवाइज्ड योजना पेश करेंगे”

हालत में इसे नहीं होने दिया जाएगा। हाईकोर्ट में ये निर्देश नहीं दिए कि नाले की चौड़ाई 30 मीटर की जाए इसके दोनों तरफ 10-10 मीटर सड़क बनाने का जिम्मा है।

मकान तोड़कर सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इस इलाके में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाया जाएगा बीजेपी राज में इसके लिए अमृत योजना में 21 करोड़ मंजूर किए थे और मैन उद्घाटन किया। सरकार बदलने के बाद कांग्रेस राज में यह कहकर इसे बंद कर दिया कि जमीन नहीं है। 30 कॉलोनियों के लोग बदनू से परेशान हैं, यहां एसटीपी बनाया चाहिए।

यूडीएच मंत्री डाक्टर सिंह खर्रा ने कहा कि पीआईएल पर सुनवाई करते हुए 2018 में हाईकोर्ट ने नाले को पक्का करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। अब 2018 से लेकर अब तक जो हुआ उस पर कमेंट नहीं करूंगा। इस पर तोचते हुए सराफ ने कहा कि जनता को तब पता लगता है जब लाल निशान लगे। खर्रा ने कहा कि एक बार हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में कार्य योजना पेश कर दी। अब हाईकोर्ट से इसमें संशोधन का आग्रह करेंगे। हाईकोर्ट अनुमति दे देना तो ऐसी कोई नई कार्ययोजना बनाकर पेश करेंगे, ताकि कम से कम लोगों को परेशानी हो।

का क्या औचित्य है? लोकतंत्र में 500 मकानों को तोड़ना संभव नहीं है, किसी

ऑडिट कार्य में लापरवाही बरतने पर 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों पर कठोर कार्यवाही

जयपुर। सहकारिता विभाग में ऑडिट कार्य में लापरवाही बरतने पर 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को वर्तमान गठित पैन्ल से हटाते हुए भविष्य में गठित किए जाने वाले पैन्ल में शामिल करने पर रोक लगाई गई है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों मंजू राजपाल द्वारा इस सम्बन्ध में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है।

■ सहकारिता विभाग ने वर्तमान गठित पैन्ल से हटाया, भविष्य में पैन्ल में शामिल करने पर रोक लगाई

2023-24 तक ऑडिट कार्य में उक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों की लापरवाही सामने आई थी। जांच परिणाम के आधार पर कार्यवाही करते हुए मै. विभोर रूपेश एण्ड कम्पनी, मै. रतन गर्ग एण्ड एसोसिएट्स, मै. गोयल नागपाल एण्ड कम्पनी, मै. राकेश लालगढ़िया एण्ड एसोसिएट्स, मै. भरत मूदड़ा एण्ड कम्पनी एवं देवेन्द्र भटेजा एण्ड कम्पनी को सहकारी सोसायटियों की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान गठित पैन्ल से हटाते हुए भविष्य में गठित किए जाने वाले पैन्ल में शामिल करने पर रोक लगाई गई है।

मिशन मोड में करें नवीन आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन : गालरिया

जयपुर। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं मंडल अध्यक्ष श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंडल मुख्यालय में राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 250 वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर योजना में बन रहे माही अपार्टमेंट सेक्टर-23 में एमआईजी-बी के 143 एवं समृद्धि अपार्टमेंट में एमआईजी-ए के 96 प्लेटों की स्वीकृत की गईं निविदाओं के साथ ही मण्डल की अन्य योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों पर स्वीकृति प्रदान की गई। आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2024-25 की अर्वाधि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 की एवं शेष अर्वाधि 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 की संचालक मण्डल की कार्यों पर स्वीकृति प्रदान की गई। गालरिया ने इस अवसर पर कहा कि मण्डल में चल रही

■ राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 250 वीं बोर्ड बैठक

बुधवार निलामी, प्रीमियम सम्पत्तियों के किसान कल्याण मंत्रालय, ऑक्शन तथा विभिन्न योजनाओं के प्रति भारत सरकार को पत्र आमजन का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि लिखकर खरीद अवधि आवासन मण्डल आज भी किरायाती दारों पर बढ़ाने का आग्रह किया था, अपने आवास का सपना साकार करने के लिए जिसे स्वीकार कर लिया गया आमजन की पहली पसंद है और हमें पहली है। दक ने कहा कि खरीद की पसंद बने रहने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने अवधि बढ़ाये जाने से जिला कलेक्टर के माध्यम से होंगे। उन्होंने अधिकारियों एवं अभियंतों को पंजीकरण करवा चुके नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महती योजना सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत उन वित्तीय सहायता दी जाती है, जिनमें

‘बकाया छात्रवृत्ति राशि का भुगतान मार्च तक’

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने हेतु केंद्र सरकार से 250 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की बकाया छात्रवृत्ति राशि का भुगतान मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक किया जायेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक बजट उपलब्धता में कमी होने कारण विगत पांच वर्षों में छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हो पाया। इस समस्यावधि के वित्तीय भार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिख केन्द्र की राशि उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि इस छात्रवृत्ति राशि के भुगतान पश्चात केंद्र सरकार को इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसके उपरति केंद्र सरकार से शेष रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु भी केन्द्र द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

प्रदेश में 1731 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने दी रीट परीक्षा



रीट की परीक्षा खत्म हुई तो घर लौटने वालों का रैला लग गया। जयपुर जंक्शन पर जान जोखिम में डालकर अभ्यर्थी रैलागाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे।

जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट)-2024 का आयोजन 27-28 फरवरी को सफलता पूर्वक किया गया। परीक्षा दो दिन में तीन परियों में आयोजित हुई। शुक्रवार को

आयोजित परीक्षा में 88.55 प्रतिशत परीक्षार्थियों को उपस्थिति रही। परीक्षा के लिए करीब 15 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा की पारदर्शिता एवं परीक्षा की शुचितता के लिए समस्त 1731 परीक्षा केंद्रों

पर सीसीटीवी से निगरानी की गई। रीट कार्यालय में गठित राज्य स्तरीय कमाण्ड सेक्टर एवं जिलों में अभय कमाण्ड सेक्टर से परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की गई। रीट परीक्षा में नवाचार के तहत डमी परीक्षार्थी एवं

अवांछित तत्वों पर नियंत्रण के लिए पहली बार लगभग परीक्षार्थियों के बायोमैट्रिक एवं फेस रिकग्निशन की व्यवस्था की गई। परीक्षा के दौरान सभी जिलों में तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर रहे। प्रश्न पत्रों को पूर्ण सुरक्षा के साथ परीक्षा

केंद्रों तक पहुंचाया गया वहीं परीक्षा समाप्ति के बाद ऑपेनअर शीट्स व परीक्षा सामग्री संग्रहण केंद्रों से रीट कार्यालय में पूर्ण सुरक्षा के साथ प्रेषित की गईं। गौरतलब है कि तीन साल बाद रीट की परीक्षा बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न हुई। शिक्षामंत्री

अब 10 मार्च तक हो सकेगी मूंगफली खरीद मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में किसान संघ की जिला कार्यकारिणी को 10 मार्च तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने कृषि एवं

ई.आर.सी.पी. में बांधों को जोड़ने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

जयपुर। ई.आर.सी.पी. में जयपुर जिले के बांधों को जोड़ने को लेकर भारतीय किसान संघ की जिला कार्यकारिणी को रामसुंदर बांध, बड़ा तालाबा डिफिकर्यो, खेजड़ी बांध, कोटखावदा तहसील से श्यामपुरा बांध, ठीकरियाँ मीणान बांध, दामोदरबांस का बांध, देवसी बांध और आँधी तहसील से रायावाला बांध, खल्द बांध को जोड़ने की माँग की है। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, जिला मंत्री लक्ष्मीनारायण यादव, जिला उपाध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा तिलपट्टी, जिला महिला प्रमुख यशोदा मीणा, जैविक प्रमुख कानाराम जाजरवार, जोबनेर तहसील अध्यक्ष मदनपुरी, आमेर अध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा, चामसू तहसील अध्यक्षरामोता बलारी, भगवान सहाय प्रेमपुरा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

का आग्रह किया है। इसी तरह जोबनेर तहसील का कालख बांध, पुनाना झील, डूंगरी बांध, चाकसू तहसील के रामसुंदर बांध, बड़ा तालाबा डिफिकर्यो, खेजड़ी बांध, कोटखावदा तहसील से श्यामपुरा बांध, ठीकरियाँ मीणान बांध, दामोदरबांस का बांध, देवसी बांध और आँधी तहसील से रायावाला बांध, खल्द बांध को जोड़ने की माँग की है। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, जिला मंत्री लक्ष्मीनारायण यादव, जिला उपाध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा तिलपट्टी, जिला महिला प्रमुख यशोदा मीणा, जैविक प्रमुख कानाराम जाजरवार, जोबनेर तहसील अध्यक्ष मदनपुरी, आमेर अध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा, चामसू तहसील अध्यक्षरामोता बलारी, भगवान सहाय प्रेमपुरा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

अब 10 मार्च तक हो सकेगी मूंगफली खरीद मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में किसान संघ की जिला कार्यकारिणी को 10 मार्च तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने कृषि एवं

आदिवासियों के अलग धर्म कोड पर विधानसभा में नोकझोंक

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर। विधानसभा में जनजाति विकास और सामाजिक न्याय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान आदिवासियों के अलग धर्म कोड के मुद्दे पर कई बार नोकझोंक और हंगामा हुआ। गणेश घोषरा सहित कई कांग्रेस विधायकों ने अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग उठाई। बीजेपी विधायकों ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और प्राचीन समय से हिंदू धर्म से जुड़े हैं, रामायण और महाभारत में भी इसके प्रमाण मिल जाएंगे। ज्ञात रहे कि आदिवासी इलाके के कांग्रेस और बीजेपी के विधायक अलग आदिवासी धर्म कोड की पहली भी मांग करते आए हैं।

■ जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते वे एसटी आरक्षण, टीएसपी का फायदा छोड़ें : समाराम गरसिया

बहस में भाजपा विधायक समाराम गरसिया ने कहा कि, आदिवासी का कोई धर्म कोड नहीं, वह हिंदू है। अंग्रेज यह सब लाए, आदिवासी गर्व से कहता है कि वह हिंदू है। उन्होंने कहा- जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते वे एसटी आरक्षण और टीएसपी का लाभ छोड़ दें। उन्हें दो धर्म का लाभ थोड़े ही मिल सकता है। जो खुद हिंदू

नहीं है तो एसटी आरक्षण का फायदा क्यों ले। आदिवासी परंपरागत हिंदू है। उधर कांग्रेस विधायक गणेश घोषरा ने कहा कि, आदिवासियों का अलग से धर्म कोड लागू होना चाहिए। जब बौद्ध, जैन धर्म का अलग से कोड है तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं है। आदिवासियों को यह मांग लंबे समय से की जा रही है। आदिवासियों को टीएसपी क्षेत्र में नौकरियों का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है।

जयपुर। मेट्रो-द्वितीय की कॉमर्शियल कोर्ट-एक ने सांगानेर की अपशिष्टों के जल उपचार व प्रबंधन के लिए बनाए सीईटीपी की निर्माण राशि व इससे जुड़ी करीब 96 करोड़ रुपए की वसूली मामले में आदेश की पालना नहीं करने पर जयपुर कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर सहित पांचयून कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी की अवमानना नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इनसे एक मार्च को स्पष्टीकरण देकर यह बताने के लिए कहा है कि उन्होंने 14 फरवरी 2025 के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना क्यों की और क्यों ना इसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने यह निर्देश मैसर्स एडवर्ट पैराथयरकेयर टेक्नोलॉजीज के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया। कोर्ट ने कहा कि अर्वाड होल्डर की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा कि उन्होंने कोर्ट के सेल अमीन को सहयोग नहीं किया और इसके चलते ही उसने कुर्क वार्ड को बिना तामील ही कोर्ट में वापस किया है। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उन्होंने जानबूझकर आदेशों की अवहेलना की है, इसलिए वे स्पष्टीकरण दें।

मदन दिलावर ने रीट के निर्विघ्न संचालन पर हर्ष जताया है। शासन सचिव, शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने तीन साल बाद निर्विघ्न रूप से संचालित हुई रीट के लिए सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है।

कुछ लोग राष्ट्रीय एकता पर राजनीतिक टिप्पणी से नहीं चूकते : शेखावत जयपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय एकता पर राजनीतिक टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। शेखावत ने शुक्रवार शाम जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की हिंदी के विरोध में आई प्रतिक्रिया पर शेखावत ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको पहले हिंदी के विषय में जानना चाहिए। हिंदी पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा है। मां भारती के भाल की बिंदी है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उस पर इस तरह की टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। स्थानीय लोगों की भावनाओं को उकसाना गलत है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि जिस देश के लोकतंत्र को 75 साल हो गए हैं, उस देश में न तो ऐसे विधायक के लिए कोई स्थान होना चाहिए और न ही ऐसी भाषा बोलने वाले लोगों के प्रति कोई आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए।